>

Title: Need to regularize all unauthorized colonies in National Capital Territory of Delhi.

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर पूर्व दिल्ली): सभापति जी, मैंने जो नोटिस दिया है, वह दिल्ली में अनॉथराइज़्ड कॉलोनीज़ के रैगुलराइज़ेशन के संबंध में है। दिल्ली में 1600 के करीब ऐसी कॉलोनियाँ हैं जिनको एक पॉलिसी के तहत केन्द्र सरकार ने कहा कि हम उन्हें रैगुलराइज़ करेंगे। हमारी कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी के हाथ से उनको करीब पाँच साल पहले सर्टिफिकेट भी दिलाए गए। यहाँ पूर्वांचल के बहुत लोग रहते हैं। ज्यादातर वे ही लोग वहां आकर बसे हैं। अब इन कॉलोनियों का बुरा हाल है। किसी को मालूम नहीं कि वह क़ॉलोनी किस स्तर पर है और उनके लिए क्या किया गया है। कोई कहता है कि सौ कॉलोनियाँ पास हो गई हैं, कोई कहता है 150 पास हो गई हैं, कोई कहता है कि 600 पास हो गई हैं। अगर पास हो गई तो उनमें काम नहीं हो रहे हैं। केन्द्र सरकार के अधीन यह सारा मसला आता है। मेरी पुरज़ोर मांग है कि आप एकमुश्त यह काम करें, एक केन्द्रीय डिपार्टमैंट बनाकर उसके अधीन ये 1600 कॉलोनीज़ ले लें। आप जो कह रहे हैं कि 2007 की कट ऑफ डेट रखेंगे, मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। पाँच साल हो गए और पाँच साल में उन कॉलोनियों का विस्तार हुआ है। अगर विस्तार हुआ है तो उसकी कट ऑफ डेट आप 31.12.2012 रखें। आप यह नहीं कह सकते कि 1.1.2013 हो लेकिन अगर आप कहेंगे कि दस साल पहले या पाँच साल पहले हमने कट ऑफ डेट रखी है तो लोग मर जाएँगे। उनके मकान आपको तोड़ने पड़ेंगे। यह नहीं हो सकता। जो मकान बन गए, वह बन गए और मकान आसानी से नहीं बनते।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : अभी कुछ मकान तोड़ भी दिये हैं।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : इसीलिए मैं कह रहा हूँ। यह इनकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात यह है कि दिल्ली सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि एकमुश्त सारे काम हो सकें। तो वे टुकड़ों में काम करेंगे। टुकड़ों में काम करेंगे तो लोग सालों नारकीय जीवन बिताएँगे। केन्द्रीय सरकार अगर डिपार्टमैंट बनाकर अपने हाथ में ले ले और एकमुश्त पैसा उसमें खर्च करे, उसका विकास करे, सीवर, सड़क, बिजली, पानी, कम्यूनिटी सैन्टर, डिसपैन्सरी और स्कूल - जब तक आप इन सब चीज़ों का एक साथ विकास नहीं करेंगे, उनको कोई राहत मिलने वाली नहीं है। हम उनको दयनीय स्थिति में नहीं रखना चाहते। सरकार उनको कोई भीख नहीं दे रही है। सरकार उन पर कोई ऐसा अहसान नहीं कर रही है कि सरकार आउट ऑफ द वे जाकर कोई काम कर रही है।

इसलिए मेरी पुरज़ोर मांग है कि आप मेरी बात मानेंगे, एकमुश्त पैसा देंगे, डैवलपमैंट करेंगे, और सैलैक्टिव डैवलपमैंट नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे अपने क्षेत्र में 200 अनॉथराइज्ड कॉलोनीज़ हैं। मुझे बहुत दुख है कि दूसरी जगह तो काम हो रहा है लेकिन मेरे यहाँ काम नहीं हो रहा है। नीचे के जो अधिकारी होते हैं, ये फाइलों को घुमाते रहते हैं। ...(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूँ कि नीचे कुछ अफसर होते हैं जो काम नहीं करते। मेरी पुरज़ोर मांग है कि जहाँ भी विकास हो, एक साथ विकास हो, एकमुश्त पैसा दिया जाए और उन लोगों को राहत दी जाए।